

न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:-श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-131/2022

जीसीएमएस नं. :-2022/356

श्रीमती बिन्दु कौर पत्नी लालसिंह जाति मजहबी निवासी चक 24 एएस -सी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

--- प्रार्थीया

बनाम्

1. गुरसेवक सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति मजहबी निवासी चक 15 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक :- 27/09/26

:-: निर्णय :-:

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 15 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.-40/4 5 के किला नम्बर 1 ता 25 की कल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला व मुरब्बा सं.-41 पत्थर सं. 40/53 के किला नम्बर 1 ता 25 की कल 5.363 हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कल 11.688 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी मुश्तरका खाता में करनैलसिंह पुत्र साधुसिंह जाति बावरी निवासी 1 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ के नाम से 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा करनैलसिंह द्वारा अपने उक्त हिस्सा की भूमि का बैचान प्रार्थीया को करके बैयनामा दिनांक 16.06.2020 को प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया जिस पर बैयनामा के आधार पर उक्त 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है वर्तमान में प्रार्थीया उक्त 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि की खातेदार कृषक है । जमाबन्दी की प्रति सलगन प्रार्थना पत्र है । विक्रेता करनैलसिंह के द्वारा चुंकि कुल कृषि भूमि मे से अपने 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कषि भूमि का बैचान प्रार्थीया को करके उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीया को मौका पर बैयनामा दिनांक 16.6.2020 के रोज ही सौंप दिया था प्रार्थीया यहां यह स्पष्ट करती है कि विक्रेता करनैलसिंह का अपने सह काशतकारान के साथ उक्त सयुक्त खाता की कुल कृषि भूमि का पारस्परिक तौर पर घरेलू बटंवारा हो रखा था जिस घरेलू बटंवारा में विक्रेता करनैलसिंह के धारण एवं कब्जा में चक 15 एच तहसील अनूपगढ़ का



सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़



मरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.40/45 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मुरब्बा सं. 41 पत्थर सं 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कुल 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कब्जा काशत में थी तथा वरवक्त बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को विक्रेता करनैलसिंह ने घरेलू बटंवारा अनुसार अपने कब्जा काशत के उक्त किलाजात का कब्जा मौका पर प्रार्थीया को सौंप दिया था तथा अपने नाम की पानी की परची भी प्रार्थीया को सौंप दी थी जिस पर तब से लेकर आज रोज तक प्रार्थीया का विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीया शके कब्जा.काशत है। प्रार्थीया निवेदन करती है कि विक्रेता करनैलसिंह द्वारा वरवक्त बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को घरेलू बटंवारा मुताबिक अपने हिस्सा व कब्जा की चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं. 40/45 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मुरब्बा सं. 41 पत्थर स 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कल 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी का कब्जा मौका पर प्रार्थीया को सौंप दिया था जिस पर तब से लेकर प्रार्थीया का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है लेकिन पूर्व में उक्त विवादित भूमि के एक सह काशतकार लालचन्द पुत्र गोविन्दराम जाति नायक निवासी 15 एच तहसील अनूपगढ द्वारा प्रार्थीया के कब्जा काशत की उक्त विवादित भूमि पर दखलन्दाजी पैदा करने पर प्रथीया द्वारा लालचन्द के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्नतगत धारा 188 आर टी एक्ट श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया तो वाद अनवानी बिन्द्रकौर बनाम लालचन्द आदि वाद सं. 37/2020 पर संस्थित हुआ । तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं. 37/2020 प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 28.07.2021 को निर्णित एवं डिक्रित किया जाकर अप्रार्थी लालचन्द को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि "अप्रार्थी सं 1 विवादित कषि भमि वाके चक 1 5 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं. 40/45 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मरब्बा सं. 41 पत्थर सं 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 1 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कल 5.525 हैक्टर पर प्रार्थीया के कब्जा काशत, उसके उपयोग उपभोग एवं उसके लिए प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से बाज वा ममनू रहे " निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 सलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त प्रार्थना पत्र के दौरान ही उक्त संयुक्त खाता के पूर्व सह काशतकार लालचन्द पुत्र गोविन्दराम द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बैचान अप्रार्थी सं. 1 को कर दिया और वर्तमान में लालचन्द का हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है चूंकि अप्रार्थी सं. 1 उक्त सयुक्त खाता की भूमि का सह काशतकार बन चुका है जिसे भी प्रार्थीया के कब्जा काशत की भूमि का पूर्ण ज्ञान है चूंकि प्रार्थीया औरतजात है तथा



सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

उक्त कृषि भूमि को अपने कब्जा काश्त में लेकर अपने निर्देशन में काश्त करवा रही है जिसका वेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 अब पिछले कुछ समय से प्रार्थीया के काश्तकार के कृषि कार्य में वेजा दखलन्दाजी पैदा करने लग गया है तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त की मरब्बा सं. 41 पत्थर सं. 40/53 क किला नम्बर 2,3,4,5 की भूमि में प्रार्थीया की काश्त में, सिंचाई में दखलन्दाजी करने लग गय तथा एलानिया कहने है कि प्रार्थीया अथवा उसके किसी काश्तकार को उक्त विवादित भूमि के किला नम्बर 2,3,4,5 को काश्त नहीं करने देगा और ना ही वह न्यायालय के किसी फैसले को मानता है जबकि अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आज से अरसा पाचं रोज पूर्व भी अप्रार्थी सं. 1 ने मौका पर आकर प्रार्थीया व उसके काश्तकार के साथ झगड़ा किया उसके कृषि कार्य में बाधा पैदा करने लगा और सरेआम व एलानिया धमकी दी है कि किला नम्बर 2,3,4,5 की जमीन क प्रार्थीया चुपचाप छोड़ देवे अन्यथा वह जबरदस्ती प्रार्थीया को बेदखल कर अपना कब्जा कर लेगा जिस पर उस समय तो प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 के उक्त मकसद को विफल कर दिया लेकिन जाते समय अप्रार्थी सं.1 ने शिघ्र ही धमकी दी कि वह किला नम्बर 2,3,4,5 की भूमि प्रार्थीया को काश्त नहीं करने देगा बल्कि वह इस जमीन पर अपना कब्जा करेगा और आने वाली पानी की बारी भी वह लगाएगा तथा प्रार्थीया को बलपूर्वक बेदखल कर देगा। प्रार्थीया विवादित भूमि की खातेदार कृषक है ओर प्रार्थीया का विवादित भूमि पर शान्तिपूर्वक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीया की उक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि मे किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन अप्रार्थी सं 1 लालचवश व बेईमानी पूर्वक प्रार्थीया को विवादित कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर उस पर अवैध रूप से काबिज होने के प्रयासरत है। जबकि प्रतिप्रार्थीया को ऐसा करने का कतई विधिक अधिकार नहीं है। अगर अप्रार्थी सं.1 अपने उक्त नापाक ईरादे मे कामयाब हो गया तो इससे प्रार्थीया के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा ओर प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि पर अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थी क पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं 1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं. 40/45 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मरब्बा सं. 41 पत्थर सं. 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कल 5.525 हैक्टर पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त, उसके उपयोग उपभोग एवं उसके लिए प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ



मे किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से बाज वा ममनु रहे व प्रार्थीया के काश्तकार को किसी प्रकार से तंग परेशान करने व उसके कृषि कार्य में बाधा करने से व्यादेशित रहे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिरिक्त कथनानुसार पंजीकृत बैयनामा के आधार पर मन अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि दर्ज हुई है। चूंकि अप्रार्थी विवादित भूमि का सह खातेदार है और प्रार्थीया एक खातेदार के विरुद्ध कानूनन किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से काबिले निरस्ती के है। प्रार्थीया के कथनानुसार उक्त सग्रतं खाता की भूमि का सह काश्तकारान के मध्य घरेल् बटवारा हो रखा है तो प्रार्थीया को नियमानुसार खाता विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था बल्कि प्रार्थीया द्वारा न तो खाता विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया और ना ही खाता विभाजन का अनुतोष चाह लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 188 आर टी एक्ट के वाद में ही बिना समस्तसह काश्तकारों को पक्षकार मुकदमा बनाए किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। वाद पत्र में दर्ज समस्त कृषि भूमि मौका पर सयूक्तं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसका अभी तक सह खातेदारान के मध्य खाता विभाजन नहीं हुआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि अपीलाधीन भूमि में किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक सहकारतकारी भूमि के प्रति इन्च पर कब्जा होता है ऐसी स्थिति में बाद खाता विभाजन प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के वाद सं. 37/2020 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है जिसमें न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.1.2022 को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 की क्रियाविन्ती स्थगित रखने के स्थगन आदेश प्रदत्त किए गए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीया के जवाब एवं स्टेट जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:-

प्रथम दृष्टया प्रकरण :- यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीगण का हित


सुरेश कुमार
उपखण्ड अधिवक्ता
अनूपपण्ड

निहित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते हैं कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह-खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता और ना ही सह-खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह-खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

सुविधा का संतुलन:—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतों से वंचित हो जायें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

अपूर्ण्य क्षति:—प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके हैं तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे हैं। अप्रार्थीगण जो कि सह-खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्ण्य क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरुद्ध तय किये गये हैं। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/09/2016 को सरे इजलास सुनाया

गया।



(सुरेश राव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अनुपगढ़
अनुपगढ़